



# सम्पादकीय

## अनुरा दिसानायके : भारत के लिये मायने

ऐसे वर्क में जब दुनिया भर में दक्षिणपंथी शास्त्रकों का वर्गवय बढ़ चला है, भारत के पड़ोसी गुरुक श्रीलंका में भारतीयादी विवाहाद्या के अनुच्छेद कुमार दिसानाथके का दीवार को दाखिला पति निवाचित होना वामपंथ के लिये एक नयी बधाइ की तरह देखा जा रहा है। पूजीवादी शास्त्रन प्रणाली का लक्ष्य दौर देख चुके इस छोटे से देश ने 55 वर्षीय दिसानाथके पर एक इस्तीलिये भएसा नहीं जताया है क्योंकि वे एक नजदीके बेटे हैं, बल्कि उन्हें भास्तवाद से लड़ने तथा आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाले दाखिलाध्यात्मके रूप में भी देखा गया है। देश के इतिहास में पहली बार दो दौर की नवगणना के बाद इस पद के लिये हुए चुनाव पर दिसानाथके को जीत इस्तीलिये सायिल हुई क्योंकि शीर्ष पर एक दो उम्मीदवार आवश्यक 50 प्रतिशत वोट प्राप्त नहीं कर सके। उत्तर-भारतीय श्रीलंका के एक गांव थम्बुटेगामा के अनुच्छेद दिसानाथके जनता विमुक्ति पेट्रुमूना (जेवीपी) के नेता हैं जिसने नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन किया हुआ था। 2019 के चुनाव में महज 3 प्रतिशत वोट पाने वाले दिसानाथके ने अबकी 42.31 फीसदी जत प्राप्त कर अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी सर्वीय प्रेमदाता (32.76 प्रश्न) को काफी पीछे छोड़ दिया। सोलगार को उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली इन दिनों अमेरिका की यात्रा कर एक प्रधानमंत्री नेटेन्ड जोदी ने दिसानाथके को बधाई देते हुए कहा है कि: 'भारत की नेवरहुड फर्स्ट की वैदेशिक नीति और दृष्टिकोण से श्रीलंका का ख्यास स्थान है।' प्रतिसांद नें नवनिर्वाचित दाखिला पति ने भी परस्पर सहयोग के लिये अपनी प्रतिवक्षता जतलाई है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने दिसानाथके से जुलाकात कर भारत की ओर से उन्हें बधाई दे दी है। कहने को जोदी और श्रीलंकाई भास्तवादित ने एक दूसरे के प्रति सम्मान दर्शाने वाले बधाई दी है। ऐसे भौकों पर औपरिकावश ऐसे सन्नाधनापूर्ण संदेशों का आदान-प्रदान होता ही है, लेकिन देखना यह होगा कि नये भास्तवादित का भारत के प्रति और भारत का उनके प्रति नजरिया और व्यवहार क्या रहेगा। पड़ोसी गुरुकों के साथ भारत के वैसे ग्रन्थ सम्बन्ध नहीं एक गये हैं जो 2014 के पहले हुआ कर्त्ता थे, यानी कि जोदी के पीएम बनने के पहले थे। ज्यादातर पड़ोसियों के साथ किसी न किसी गुरु को लेकर भारत के सम्बन्ध सहज न एक पाने का एक बड़ा कारण इन सभी देशों पर चीन का बढ़ता प्रभाव रहा है। श्रीलंका पर भी चीन की निगाहें रही हैं। गोदावारी प्रेमदाता के वर्क चीन ने श्रीलंका के एक द्वीप हंबनटोटा को अपना सैनिक अड्डा बनाने की कोशिश की थी ताकि वह भारत और सम्पूर्ण हिन्द सागर के क्षेत्र पर दक्षिणी हिस्से से निगाह रख सके। अब आगे देखना होगा कि इसे लेकर श्रीलंका की नयी सरकार क्या कर सकती है। वैचारिक रूप से दिसानाथके के चीन के कर्तव्य बोने से इसकी आशंका तो बढ़ी है कि वे भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा तद्दीर हैं। ऐसे में भारत के लिये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कुछ विशेषकों का मानना है कि वर्तमान दौर में भारतीयों द्वारा वाम पार्टियों की भी नजदीकी है और श्रीलंका में कोई भी सरकार आये, उसे भारत को नजदीक करना मुश्किल होगा। वैसे प्रेमदाता सरकार की नीतियों तथा भास्तवाद के विवलाफ जो नेता स्वाधिक मुख्यर है, उनमें दिसानाथके अग्रणी है। उधर चीन ने इस नीतीजे पर ध्वनी जताई है। चीन के बलोबल टाइक्स ने कहा है कि 'दिसानाथके के आगे से श्रीलंका की भारत पर निर्भरता कम होगी।' वैसे पिछले दिनों जब दिसानाथके भारत के दौरे पर आये थे तब उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने भारत के साथ श्रीलंका के अच्छे सम्बन्धों का हवाला न देकर इसकी जटिलता जतलाई थी। वैचारिक रूप से दिसानाथके को भारत-विस्तृत जात्याज्ञान द्वारा है। यही जात्याज्ञान के विस्तृत जात्याज्ञान है।

नर्मदा 1312  
किलोमीटर लंबी  
बहती नदी और  
किनारे बसे पहाड़,  
जंगल ही नहीं,  
गांव- नगर, लाखों  
परिवार, उनकी  
पीढ़ियों की  
जीवनगाथा और  
चलती  
आजीविका... खेती  
, मजदूरी,  
वनोपज, मत्स्य  
व्यवसाय, या कोई  
कारीगरी की  
जटिलता और  
घाटी के संसाधनों  
पर निर्भरता,  
विशेष हकीकत  
रही। इस पर बड़े  
बांध से आने  
वाली डूब के और  
अन्य असरों के  
अध्ययनों के बिना  
ही फैसला आया,  
यह हकीकत स्पष्ट  
होती है।

**ਸਰਫਾਰੀ ਟੋਚਦ੍ਰਾਂ  
ਕੌ ਰਿਟਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ  
ਬਾਠਾਨੇ ਕੌ ਜ਼ਖ਼ਰਾਤ**



आर.के. सिन्हा

भारत अपने नागरिकों को सेहतमंद रखने के लिए तुरंत एक अहम कदम यह उठा सकता है कि वह केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं से जड़े हए सरकारी डॉक्टरों की

स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के बीच जाता है। इन पहाड़ियों की 7वीं पहाड़ी की ओर का दिव्य मंदिर स्थित है, जो कि अद्भुत भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर या वेंकटरामण में अधिकांश लोग जानते हैं। इसी दिव्य करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य मंदिर के दर्शन स्थापित भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी सनातन धर्म संस्कृति व परंपराओं में ऐसा के लिए इस क्षेत्र के ही 'स्वामी पुष्करणी' है। सरोवर तिरुमला के पास ही स्थित है। जिकि यहां आने के पश्चात व्यक्ति के जीवन मम-मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। चरणों में स्थान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त 133 में तिरुपति बालाजी के इस मंदिर का लिया था और रोजर्मार्ग के कार्य संपन्न 'मुलामा-तिरुपति' का गठन करके उसके बाहर।

तो इस प्रबंध समिति का पुनर्गठन किया प्रदेश सरकार के एक प्रशासनिक दिया गया, जब से ही इस प्रबंध समिति द्वारा मंदिर से जुड़े हुए हर प्रकार के कारों हां आपको बता दें कि इस दिव्य अड़ अपने आराध्य के दर्शन के लिए भी अधिक श्रद्धालु देश व दुनिया से दर्शन नी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी टीटीडी की प्रसिद्ध है कि वह देश व दुनिया में बसे की संख्या में जाता है और यह प्रसाद मंदिर दी बनाया जाता है। मंदिर में रोजाना भक्तों

स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के जा जाता है। इन पहाड़ियों की 7 वर्षी पहाड़ी को का दिव्य मंदिर स्थित है, जो कि स अद्भुत भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर या में अधिकांश लोग जानते हैं। इसी दिव्य करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य मंदिर के दर्शन स्थापित भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी सनातन धर्म संस्कृति व परंपराओं में ऐसा के लिए इस क्षेत्र के ही 'स्वामी पुष्करणी' ह सरोबर तिरुमाला के पास ही स्थित है। कि यहां आने के पश्चात व्यक्ति के जीवन म-मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है चरणों में स्थान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त 1933 में तिरुपति बालाजी के इस मंदिर का लिया था और रोजर्मारा के कार्य संपन्न रुमाला-तिरुपति' का गठन करके उसके गा।

तो इस प्रबंध समिति का पुनर्गठन किया प्रदेश सरकार के एक प्रशासनिक दिया गया, जब से ही इस प्रबंध समिति द्वारा मंदिर से जुड़े हुए हर प्रकार के कारों हां आपको बता दें कि इस दिव्य अड़ अपने आराध्य के दर्शन के लिए भी अधिक श्रद्धालु देश व दुनिया से दर्शन नी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी टीटीडी की प्रसिद्ध है कि वह देश व दुनिया में बसे की संख्या में जाता है और यह प्रसाद मंदिर दी बनाया जाता है। मंदिर में रोजाना भक्तों

# सरदार सरोवर की जन्मगाथा

शुरूआत तो हुई 1959 में जब महाराष्ट्र और गुजरात एक होकर बॉम्बे सरकार थी। नर्मदा पर 'नवागाम बांध', पहले दौर में 162 फीट ही ऊंचा बनाने का प्रस्ताव हुआ और उसे बढ़ाकर दूसरे दौर में 300 फीट तक ले जाने का ! जल संसाधन और विद्युत मंत्रालय ने 320 फिट तक बढ़ाकर सौराष्ट्र और कच्छ तक सिंचाई पहुंचाने का प्रस्ताव, सलाहकार समिति की सिफारिश पर मंजूर किया। पहले दौर के निर्माण प्रस्ताव के बाद दूसरे दौर में 625 मेगावाट बिजली निर्माण भी संभव माना था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र-गुजरात स्वतंत्र राज्य बनने के बाद 1963 में केंद्रीय मंत्री डॉ. के. ए.ल. राव ने 425 फिट का नवागाम बांध और पूरा लाभ गुजरात को तथा 850 पूर्ण जलाशय स्तर का पुनासा बांध (आज का इंदिरा सागर!) और उससे लाभों का बट्टवारा मध्यप्रदेश और गुजरात में 2:1 मंजूर करवाया; 'भोपाल अनुबंध' के रूप में। मध्यप्रदेश शासन ने बाद में इसे नामंजूर करके विवाद उठाया और खारिज करवाया। इसके बाद शुरू हुआ आंतरराज्य विवाद, जिसके निराकरण के लिए इंदिरा गांधी ने गठित किया ट्रिब्यूनल, जो 1969 से 1979 तक चला। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों राज्यों ने 10 साल तक गुजरात में नर्मदा पर बड़ा बांध बनाने का विरोध दर्ज किया। मध्यप्रदेश में चला सर्वदलीय निमाझ बचाओ आंदोलन !

दिसंबर 1979 म आतराज्य नमदा ट्रॉब्यूनल याने जल विवाद न्यायाधिकरण का फैसला आया, जो परियोजना के विविध पहलू और असरों के अध्ययन पूरे करे बिना, विवाद के निराकरण का निर्णय था। 10 सालों के कार्यकाल में न्यायाधिकरण के सदस्यों ने नर्मदा घाटी की मुलाकात ली, वह मात्र शूलपाणीश्वर, हापेश्वर और कोटेश्वर मंदिरों तक सीमित थी, न ही किसी विस्थापित होने वाले गांव या परिवार की। महाकाय योजना को दी मंजूरी और साहूकारी भी बिना अध्ययन।

नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी बहती नदी और किनारे बसे पहाड़, जंगल ही नहीं, गांव-नगर, लाखों परिवार, उनकी पीढ़ियों की जीवनगाथा और चलती आजीविका...खेती, मजदूरी, बनोपज, मर्स्य व्यवसाय, या कोई कारीगरी की जिलता और घाटी के संसाधनों पर निर्भरता, विशेष हकीकत रही। इस पर बड़े बांध से आने वाली झुब के और अन्य असरों के अध्ययनों के बिना ही फैसला आया, यह हकीकत स्पष्ट होती है।

राष्ट्रीय स्तर पर 1993 में ही, विस्थापितों के अधिकार झुबाते हुए धकेले जाते बांध के

A wide-angle photograph of the Dhuandhar Dam, a large concrete gravity dam with multiple vertical gates across a wide river. The dam is set against a backdrop of hills and a clear sky. In the foreground, there are some trees and a small structure near the water's edge.

प्रोग्रेस में 1985 से शुरू हुए सतत सत्याग्रह, पवास आदि के बाद नर्मदा आदोलन से एक विशेष चुनौती दी गई, जलसमाधि घोषित करकर ! उसके पहले 1988 का धरना और लियां, 1989 में 80 किलोमीटर चले आदिवासी और वाहनों से पहुंचे मध्यप्रदेश के मामाडलासियों की हजारों की संख्या में अंधस्थल पर गिरफ्तारी हुई थी। 1990 में बाबा आपटे जी के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री वास पर सत्याग्रह और बहुगुणाजी, सुगथा नमारी जैसे की उपस्थिति में चर्चा; मुंबई के 8 दिन के उपवास के बाद शरद पवार जी का अंधस्थल पर पहुंचकर गुजरात और महाराष्ट्र 5 अधिकारियों सहित बैठक और पुनर्वास के बना बांध आगे न बढ़ने देने की घोषणा... सब चुका था। 1990 में ही 5000 विस्थापितों ने पैदल जनविकास मार्च और उस पर हुए मन के साथ 21 दिनों का उपवास देश और निया से सहयोग पा चुका था ! फिर भी ढूब गया खतरा, पहाड़ी आदिवासियों पर छाते हुए बैठक जल समाधि का निर्णय लिया गया, तभी जना आयोग के उपाध्यक्ष जयंतराव पाटिल भी की अध्यक्षता में बना 'पांच सदस्यीय 'मूह' जो जल संसाधन मंत्रालय के प्रमुख चिवर हो गमस्वामी अच्यर, अर्थशास्त्री एल. डॉ. जैन, वसंत गोवारीकर, कुलदै स्वामी जैसे बांदोलन और शासन से प्रस्तावित मान्यवरों ने था। दोनों पक्षों की सुनवाई और प्रस्तुतियों ने बाद उनका भी निष्कर्ष रहा, सरदार सरोवर नियोजन में अधूरापन और लाभों के गलत विवरों का 100 साल में 75 नहीं, मात्र 61 वर्ष ही भर सकते हैं, अपेक्षित लाभ, यह गवाद मिल सकते हैं, अपेक्षित लाभ, यह इहते हुए पर्यावरणीय और सामाजिक निपूर्ति याने पुनर्वास के भी अन्ये नियोजन एवं कड़े सवाल उठाने वाली उनकी रिपोर्ट गासकों को स्पष्ट चेतावनी देंगी रही !

गों मैकिना का हो दे हैं। सत्तरी के गा... सत् स

दे 1990, 1992 से लेकर 2004 तक आदेश निकाले ! वनगांवों में कसते आए आदिवासियों को हक नवास का। 'टापू' में आते आदिवासी में हरते आदिवासियों का भी पुनर्वास नेकिन आज तक जारी है, संघर्ष और ग्री ! करीबन 200 परिवारों को आधाहक मिला है।

हीं मिली पूरी या सही भूमि, वे मूलगांव केनारे है, साल-साल डूब भुगते हुए, तो ! कुछ आदिवासी बुजुर्ग गुरज गये, लने के पहले... कुछ फंसे हुए हैं, में आर्बंटिट काश्त के लिए अनुपयोगी सिंचित जमीन पाक ! महाराष्ट्र का मतदार जिस गांव में है, उस 'मणिकेली' से दुनिया के 2000 संगठनों ने परित्यक्त प्रस्ताव, माद्रिट, स्पेन में विश्व बैंक साल पूर्ति पर उन्हें चुनाती देते हुए। भी मणिकेली में जो बचे हैं परिवार, वे 93-94 में डूब भुगते थे और आज भी इड की चेटियों पर रहकर, पानी, रस्तों की समस्या भुगतते ! मध्यप्रदेश अन्याय भुगत रहे हैं, ऐसे कई सी, दलित, सभी समुदायों के, 1994 से पहाड़ि क्षेत्र में, तो मैदानी में 2000 से डूबग्रस्त होकर भी नहीं हैं। डूब की भूमि के बदले भूमि ने पर 60 लाख रुपए (5 एकड़ के देने के सुप्रीम कोर्ट के 2017 के के पालन के लिए सैकड़ों रुके हैं, एकल महिलाओं थी !

में विवाद निराकरण ही उद्देश्य होते बूनल का फैसला, उसमें निर्देशित के प्रावधान भी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र रहे हैं, गुजरात के लिए नहीं ! अखिर बैंक के दबाव से गुजरात को पारित होड़े कई आदेश, जिससे गुजरात में

पुनर्वासित, गुजरात के या महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के (जिहें स्वेच्छा निर्णय का अधिकार है) विस्थापितों को भी ट्रिब्यूनल आदेश जैसे और अन्य अधिकार भी मंजूर हुए। उन्हें प्राप्त करने में भी आई समस्याएं-आर्बंटि भूमि, भूखंड या सुविधाओं संबंधी- जो आज तक भुगत रहे हैं, सैकड़ों आदिवासी ! तीनों राज्यों में भूतपूर्व न्यायाधीशों को सदस्य बनाकर सर्वोच्च अदालत में आंदोलन की याचिका पर सुनवाई के दैरान जो गठित हुआ, वह शिकायत निवारण प्राधिकरण आज कैसा कमज़ोर साबित हो चुका है। आज भी कभी नर्मदा घाटी के 7 बांध रह करना, फिर वर्षों बाद मंजूर घोषित करना हो रहा है। घाटी के ऊपरी बांधों को पर्यावरणीय शोध और मंजूरी के बिना आगे ध्वेकलना जारी है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 'पेस' कानून का उल्लंघन करके जारी है। यह सब कुछ कानून, नीति के साथ जुड़ा अधिकार कुचलकर जब आगे बढ़ता है, तब देशभर के उजाड़े गये करोड़ों लोगों की (जिनमें 1985 के गृह मंत्रालय के अहवाल अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक आदिवासी ही थे) जिंदाबाद बर्बाद होते देखेने- जनने वाले तो चुप नहीं बैठ सकते ! सरदार सरोवर के किसी भी प्रभावित को तात्कालिक या कायमी डूब से विस्थापित नहीं होने देना, और डूब के कम से कम 6 महीना पहले पुनर्वास पूरा करना, ऐसे कानूनी आदेश को हर न्यायिक आदेश में दोहराने पर भी सर्वोच्च न्यायालय की खुली अवमानना करने वालों पर कौन उठायेगा न्याय का डंडा ताकि बचेगा विकास के दायरे में भी संविधान का फंडा ? करोड़ों की पूंजी और अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लगाकर, आशा रखते हैं राजनेताओं से मतदाता और कई कार्यकर्ता भी, 'जनप्रतिनिधित्व' में ! प्रत्यक्ष में कौन से सवाल छुड़वा सकते हैं, विधानसभा और लोकसभा में भी ? विस्थापितों का त्याग चाहने वाले उन्हें नहीं मानते 'पूंजी' निवेशक !

अपना जल, जंगल, जमीन देने वाले, किसी खदानों के लिए अपनी धरा के नीचे सम्झाली खनिज संपदा को दान करने वाले, प्राकृतिक पूंजी का और परियोजना पर दिन-रात पसीना बहाने वाले श्रमपूंजी का निवेश ही करते हैं। मात्र वित्तीय पूंजी या हवाई माध्यमों से तकनीकी ज्ञान की पूंजी लगाने वालों को ही मानते हैं विकास नियोजक, विकाससाधक ! कोई प्रश्न उठाते ही 'विकास- विरोधी' से लेकर 'अर्बन नक्सल' तक जाहिर करना, अब विकास को मंत्र बनाकर चल रही राजनीति के तहत चुनावी खेल होता है। उसे जीत-हार तक पहुंचाना हो, तो जरूरी है खुली सार्वजनिक बहस !

कते हैं कि देश के हेल्थ सेक्टर में की संख्या में वृद्धि लगातार होती इस बात को ध्यान में रखते हुए यह शिक्षित करना होगा कि अनुभवी और डॉक्टरों के अनुभव का लाभ देश के सेक्टर को मिलता रहे। यह बात कहीं जा रही है, क्योंकि अनुभव ई विकल्प नहीं हो सकता है। मेडिकल एसेसिएशन (मए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय न मानते हैं कि सरकारी डॉक्टरों की वृत्ति की आयु बढ़ाकर 70 करने से ल अनुभवी डॉक्टरों की कमी दूर लिक; युवा चिकित्सकों को जरूरी न भी मिलता रहेगा। ल मेडिसन की दुनिया में अनुभव त अधिक महत्व होता है। यहां पर जब कोई नौजवान मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है, उसके बाद वह अपने अध्यापकों के अलावा वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों के संपर्क में लगातार रहता है मार्गदर्शन के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुभव का लाभ समय तक लाभ उन्हें मिलता रहे जो इस पेशे में आ रहे हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुभव और इस पेशे में आए नए डॉक्टर मिल-जुलकर मरीजों के रोगों के उपचार को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस रोशनी में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाना एक जरूरी कदम हो सकता है। चूंकि डॉक्टर अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं इसलिए वे 70 साल की उम्र तक तो पूरी तरह से काम करने लायक होते हैं।

# धर्म को मिले सख्त सजा

धर्म के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बनाया जाता है, उसके चलते अब वह आ गया है जब सनातनियों को संवैधानिक सरक्षण देने के लिए केंद्रीय व राज्य के 'सनातन धर्म कार्य मंत्रालय' जो कि सनातन धर्म के हित से जुड़े हुए सभी को देखें और उनके हितों की रक्षा करें जरूरी है।

इस सरकार के इस मंत्रालय के अधीन 'सनातन धर्म रक्षा बोर्ड' का गठन हो, जो धर्म से जुड़ी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं अदि की रक्षा करते हुए धर्म की रक्षा करने करें। वहीं देश व दुनिया में सनातन धर्म के सभी छोटे-बड़े, प्राचीन व नये धार्मिक व रक्षा के लिए 'देवस्थान रक्षा बोर्ड' का गठन होना जरूरी हो गया है, जिससे इन जगतों का सही ढंग से रखरखाव हो और भक्तों को सही ढंग से सुविधाएं प्राप्त हो पाएं। अब यह आ गया है जब देश में उपरोक्त सभी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए लल्द अस्तित्व में लाया जाए और उनके द्वारा सनातन धर्म को संवैधानिक रूप से देकर के देश व विदेश के स्तर पर बार-बार रची जा रही साजिशों से भविष्य में जाए। वैसे भी विश्व के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म के अनुयायियों का धर्मप्रष्ट साजिश हजारों वर्षों से होती आ रही है। लेकिन फिर भी सनातन धर्म अपने मूल्यों और अपनी दैवीय शक्ति के दम पर पूरी दुनिया में अपना एक अहम विशिष्ट जग भी बनाए हुए है। सनातन धर्म के लगातार देशी विदेशी घट्यंत्रकारियों के द्वारा रहने के बावजूद भी उसकी धर्म ध्वजा आदिकाल से गर्व से लहराती आ रही है।

वजह से ही कुछ विधर्मी लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए तरह-तरह विश्व रखते रहते हैं, अभी हाल ही में विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वालाम के लड्याँ में जानवर की चर्चा व मछली का तेल युक्त धी मिलने की घटना भी हो गई। उस तरह की किसी साजिश का हिस्सा ही लगती है। इस धर्मप्रष्ट करने की घटना पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। इस मिलावटखोरी की घटना को लेकर देश व बासे हुए सनातन धर्म के अनुयायियों में बेहद गुरसा व्याप्त है, वह यह जानना कि देवालय के प्रसाद को निशाना बनाकर के धर्मप्रष्ट करने का दुसाहस करने की विश्वासी विस्तारी है। जब से सनातनियों की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी के मिलावट की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, तब से ही करोड़ों सनातन धर्म के प्रेमियों की इस घट्यंत्रकारी को ढूँढ़ रही है।

## तिरुपति बालाजी- सनातन धर्मियों की मांग भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को मिले सख्त सजा



आंध्रप्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित पहाड़ियां शेषनग के 7 फनों के नाथार पर बनी हुई है, उनको 'सप्तगिरि' कहा जाता है। इन पहाड़ियों की 7 वीं पहाड़ी र ही भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर या बालाजी का दिव्य मंदिर स्थित है, जो कि वेंकटाद्री' के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैसे तो इस अद्भुत भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर या बालाजी के मंदिर की महत्ता को देश व दुनिया में अधिकांश लोग जानते हैं। इसी दिव्य अहिमा के चलते ही देश व दुनिया से हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य मंदिर के दर्शन न आने के लिए आते हैं। इस भव्य दिव्य मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी ने भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। सनातन धर्म संस्कृति व परंपराओं में ऐसा जाना जाता है कि भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र के ही 'स्वामी पुष्करणी' अम्बक सरोवर के किनारे निवास किया था, यह सरोवर तिरुमाला के पास ही स्थित है। स दिव्य अद्भुत मंदिर के संर्दह में मान्यता है कि यहां आने के पश्चात व्यक्ति के जीवन पर के सभी पाप धूल जाते हैं और उसको जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और वह भगवान के तिरुपति बालाजी के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहरा है। भारत की आजादी से पहले वर्ष 1933 में तिरुपति बालाजी के इस मंदिर का धर्म प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और रोजर्मार्ट के कार्य संपन्न नहरने के लिए एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति 'तिरुमाला-तिरुपति' का गठन करके उसके धर्म में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया गया था।

तीकिन जब आंध्रप्रदेश राज्य का गठन हुआ तो इस प्रबंध समिति का पुनर्गठन किया गया और इस मंदिर की प्रबंध समिति में आंध्र प्रदेश सरकार के एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जब से ही इस प्रबंध समिति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् (टीटीडी)’ के द्वारा मंदिर से जुड़े हुए हर प्रकार के कार्यों को निर्बाध रूप से संपन्न किया जा रहा है। यहां आपको बता दें कि इस दिव्य मलाईक क्षेत्र में रोजाना भक्तों की भारी भीड़ अपने आराध्य के दर्शन के लिए आमंडती है, इस मंदिर में लगभग 50 हजार से भी अधिक श्रद्धालु देश व दुनिया से दर्शन करने के लिए आते हैं। इन सभी श्रद्धालुओं की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी टीटीडी की होती है। मंदिर के श्रीवारी लङ्घु का प्रसाद इतना प्रसिद्ध है कि वह देश व दुनिया में बसे हए करोड़ों भक्तों के पास रोजाना लाखों लङ्घु की संख्या में जाता है और यह प्रसाद मंदिर बंध समिति के द्वारा स्वयं की रसोई में खुद ही बनाया जाता है। मंदिर में रोजाना भक्तों

की भारी भीड़ होने के चलते मंदिर प्रबंध समिति के पास रोजाना ही भारी मात्रा में धन लैलत व खाने पीने और इस्तेमाल करने का सामान आता है, उस सबके बावजूद भी मंदिर प्रबंध समिति सनातन धर्म के करोड़ों अनुयायियों की आस्था की रक्षा करने में गाकाम रही है एक रिपोर्ट के अनुसार मंदिर का लड्डूओं का यह प्रसिद्ध प्रसाद धी की जगह जानवरों की चर्बी व मछली के तेल में बन रहा है, इस लड्डू के प्रसाद ने दिव्य मंदिर की प्रवित्रता को चोट पहुंचाते हुए ना जाने सनातन धर्म के कितने शाकाहारी अनुयायियों का धर्मग्रह करने का दुस्साहस किया है । लेकिन अफसोस हर माह प्रभु भक्तों से करोड़ों रुपए कमाने वाली मंदिर प्रबंध समिति उस अपार धन खाने पीने की वस्तुओं का टेस्ट करने वाली एक स्थाई लैब तक निर्माण भी आजतक नहीं कर पाई । प्रसाद में जानवर की चर्बी व तेल की मिलावट का यह खेल हिन्दू धर्म के भक्तों की बाबानाओं से खिलवाड़ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है ।

लेकिन आज विचारणीय तथ्य यह है कि 'सनातन धर्म' के अनुयायियों के अपने ही प्यारे दश में ही उनकी आस्था पर बार-बार प्रहार किया जा रहा है । कभी उनकी तुलना मच्छरों की जाती है । कभी उनके धार्मिक परंपराओं, रीति-रिवाजों व संस्कृति पर प्रश्नचिन्ह तंगाया जाता है । कभी पूरी धर्म को पाखंड बताने का दुस्साहस किया जाता है । कभी कहा जाता है कि ऐसा कोई धर्म ही नहीं है । कभी सनातन धर्म में पूजनीय गाय माता को कर्साइखाना में काटा जाता है । कभी राजनेताओं के द्वारा अपने क्षणिक स्वार्थों को पूरा

करने के लिए सनातन धर्म के अनुयायियों में जाति के नाम पर फूट डालकर के उन नोंगों को जातियों में बांटेकी साज़िश रची जाती है। कभी तिरुपति बालाजी जैसे विश्व असिद्ध मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्ची व मछली के तेल की मिलावट करके उनके धर्मप्रष्ट करने की गंभीर साज़िश का खुलासा होता है। कभी उनके मठ मंदिरों को मिलने वाले दान का उपयोग दूसरे धर्म के लोगों के विकास पर किया जाता है। कभी सनातनिये और अपने ही देश में तरह-तरह का अंकुश लगाया जाता है। कभी उनको सप्लाई किये जाने वाला दुध, सब्जी जूस आदि तक को भी दूधित करके धर्मप्रष्ट करने की साज़िश चीज़ी जाती है। लेकिन अब विचारणीय तथ्य यह है कि आखिर कब तक यूं ही अपने ही यारे देश में हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ छल होता रहेगा और फिर भी उमरों देश के ताकतवर हिन्दू धर्म के ठेकेदार व नीति-निर्मार्ता राजनेता हमारे सनातन धर्म को संवैधानिक संरक्षण देने से बचते रहेंगे। लेकिन देश में जिस तरह से बार-बार



